प्रतिपूर्ति की जा सके और विश्व बैंक के पूंजी आधार पर पर्याप्त वार्षिक वृद्धि हो सके ।

वस्तुओं के क्षेत्र में सम्मेलन में यह सहमति हुई कि अलग-अलग वस्तुओं तथा प्रमुख वस्तुओं के संदर्भ को विकासशील देशों में बढ़ाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के ढांचे की स्थापना तथा विकासशील देशों के विपणन तथा वस्तु निर्यातों के क्षेत्र में वर्तमान कार्यक्रम को जारी रखा जाए ।

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, सम्मेलन में विकासशील देशों की प्रौद्योगिकी क्षमता को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत से कदमों पर सर्वसम्मति व्यक्त की गई तथा इसमें कहा गया कि अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट प्रणाली में आगे होने वाले संशोधन में विकासशील देशों के संबंधित मामलों को ध्यान में रखा जाए ।

महत्वपूर्ण समृद्धीय देशों ने अंकटाड-5 में वचन दिया कि वे लाइनर सम्मेलन के लिए आचार संहिता पर 1974 के संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का अनुसमर्थन करेंगे तथा उसे प्रभावी बनाएंगे और सम्मेलन में सरकारों से इस संहिता से संबंधित अभिसमय का शीघ्र कार्यान्वयन करने की दिशा में सभी आवश्यक उपाय करने के लिए कहा गया ।

सम्मेलन में, अल्पमत विकसित देशों के विकास को तीव्र करने के कार्यक्रम तथा भूबेष्ठित विकासशील देशों की विशेष आवश्यकताओं और समस्याओं से संबंधित कार्यवाही का एक व्यापक कार्यक्रम भी अनुमोदित किया गया ताकि वे अपनी भौगोलिक और अन्य बाधाओं को दूर कर सकें ।

विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग (ई सी डी सी) पर सम्मेलन में पारित किए गए संकल्प में कार्य अभिमुख प्रस्तावों को पेश करने की मांग है और अंकटाड द्वारा सहायता प्राप्त वाले विकासशील देशों की बैठकें करने की व्यवस्था है ताकि ई सी डी सी सम्बन्धी अंकटाड समिति के विशेष सत्र के संदर्भ में जो अगले वर्ष के आरम्भ में बुलाया जाएगा, विकासशील देशों के बीच व्यापार अधिमानों की विश्व व्यापी प्रणाली की स्थापना, राज्य व्यापार संगठनों के बीच सहयोग और विकासशील देशों के बीच बहुराष्ट्रीय विपणन उद्यमों की स्थापना के लिए आरम्भिक कार्य किया जा सके ।

तथापि, सम्मेलन में इस क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धि है पारस्परिक आर्थिक सहयोग तथा आत्म-निर्भरता के लिए विकासशील देशों में नई आकांक्षाएं । वाणिज्य मंत्री द्वारा रखे गए 50 अरब डालर तक की टैरिफ रियायतों के आधार पर विकासशील देशों के बीच टैरिफ सम्बन्धी वार्ताओं के एक नए दौर के विशिष्ट प्रस्ताव से विकासशील देशों के बीच और अधिक सहयोग की आशा ने जन्म लिया । ऐसे सहयोग के क्षेत्र में और बल देने के उद्देश्य से वाणिज्य मंत्री ने मेजबान देश फिलीपाइन्स के राष्ट्रपति मार्कोस और अन्य विकासशील और विकसित देशों के नेताओं से मनीला में विस्तृत विचार विमर्श किया । फिलीपाइन्स, भारत व अन्य देशों द्वारा की गई इस पहल के अनुसरण में, विकासशील देशों ने मनीला में 18 देशों की एक समिति गठित करने का विनिश्चय किया ताकि उनके बीच बहुपक्षीय आर्थिक सहयोग की रीतियों का निश्चय किया जा सके और कार्यक्रम के कार्यान्वयन को मानिटर किया जा सके । भारत की इस समिति के एक सदस्य के रूप में नामजद किया गया है ।

(ख) तथा (ग) मनीला में अंकटाड सम्मेलन के दौरान भारत ने विशेषकर सामान्य निधि को दूसरी विन्डो के लिए, जब यह स्थापित हो जाए, 50 लाख डालर के अंशदान की अपनी मंशा की घोषणा की । निधि की दूसरी विन्डो बफर स्टाक के अलावा वित्तीय उपायों में सहायता करेगी जिसको भारत बहुत महत्व देता है । ऐसी आशा है कि इससे कीमत-स्तरों को, जिनकी बढ़ती हुई प्रवृत्ति है स्थिर करने में सहायता मिलेगी तथा अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु व्यापार में विकासशील देशों की स्थिति को सुदृढ़ बनाएगी ।

Creation of posts in Customs and Central Excise Department

807 SHRI DAULAT RAM SARAN: Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE be pleased to state :

(a) the number of posts created in and above rank of Deputy Director of Customs & Central Excise, Deputy Directors, Assistant Commissioner of Income Tax and equivalent posts after the Budget Speech i e , 28th February, 1979 in which need for curtailing expenditure was stressed; and

(b) the justification for creating such posts ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : (a) The number of posts sanctioned after 28-2-79, in the grades referred to in the question is four

(b) One post of Collector has been created for the new Collectorate set up in the State of Maharashtra for better administration of the Central Excise, Customs & other allied laws. The remaining staff for this Collectorate has been found by redeployment from within the existing staff.

The Indirect Taxes Enquiry Committee and the Estimates Committee had recommended setting up a Directorate for Publications for the Customs & Central Excise. This Directorate was set up after 28-2-79 and one post of Director and two posts of Deputy Directors have been sanctioned for it.

Ex-Gratia Compensation for Properties left in East Pakistan

808. SHRI TRIDIB CHAUDHURI: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:—

(a) the total number of claims for ex-gratia relief/compensation made so far by Indian Citizens for their properties left behind in East Pakistan (now Bangla Desh) after the Indo-Pak war of 1965 and seized and disposed of by the then Government of East Pakaistan as enemy property.

(b) the total number of these claims accepted and settled for the award of ex-gratia relief by the Office of the Custodian of Enemy Property in India in accordance with the declared policy of the Government of India in this regard; and

(c) the total number of outstanding claims which still remain to be settled till to-date and how many of these outstanding claims are for amounts above Rupees one Lakh ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) The total number of claim cases, from Indian nationals/companies etc., for payment under the '*Ex-gratia*' scheme, registered since 1971, are 57464.

(b) The total number of claim cases in respect of which ex-gratia grants have been paid are 5561.

(c) The number of claim cases pending verification is 26475. It is estimated that out of these approximately 50% of the claim cases are above Rupees one Lakh.

Central credit for Smooth running of Public Distribution System

809. SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether several State Ministers have demanded for adequate Central credit for the smooth running of the public distribution system; and

(b) if so, the details thereof and Union Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Request from Maharashtra Government to lift ban on Export of Vegetables

810. SHRI V. G. HANDE : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Govrenment of Maharashtra have approached the Government of India for lifting the ban on export of vegetables and for releasing quota for this purpose; and

(b) if so, whether the ban has been lifted and quota released as requested by the State Government ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL, SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) Yes, Sir.

(b) A quota of 300 tonnes per month has been released for export by Maharashtra Agro-Industries Development Corporation subject to the condition that exports would not be more than 50% of the additional production to be undertaken by the State Government.

Introduction of a Scheme of duty Free Import against REF Licences

811. SHRI BIRENDRA PRASAD : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Union Government have a proposal to introduce a scheme of duty free import against R.E.F. licences in respect of certain commodities; and

(b) what are those commodities and what would be the impact of this measures on overall trade ?